वर्ष 5 अंक 218
पृष्ठ 18
मुजफ्फरपुर, बुधवार
8 फरवरी 2017
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 3.00

दैनिक जागरण

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अ

शिकायत मिलने पर पहले निलंबन फिर होगी जांच

जागरण संवाददाता, रक्सौल : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की समस्या का समाधान करने के लिए मंगलवार को मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क पटना प्रक्षेत्र शिवनारायण सिंह ने आदेश दिया। आधुनिक एकीकृत जांच चौकी के निरीक्षण व सीमा क्षेत्र के आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक के उपरांत बताया कि समस्या भ्रष्टाचार की जड़ है। समाधान पारदर्शिता है। स्वच्छ कार्यशैली से आयात-निर्यात बढ़ेगा। इससे राजस्व बढ़ेगा। भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड तीनों राज्यों में करीब पांच हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि किसी तरह की शिकायत मिलने पर निलंबन के उपरांत ही जांच की जाएगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। कार्य करने के लिए माइंड सेट नहीं है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। राजस्व की चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी व नेपाल में राजनैतिक नाकेबंदी का असर आयात-निर्यात पर नहीं पड़ा है। पिछले वर्ष शीपिंग से करीब 46 हजार करोड़ का कारोबार हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में 84 हजार 500 करोड़ का कारोबार हुआ। एक करोड़ 50 लाख से अधिक की नारकोटिक्स जब्ती हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में 11 हजार 800 करोड़ का निर्यात हुआ है। दिल्ली-काठमांडू को जोड़ने वाले मुख्य पथ की जर्जर स्थिति पर कहा कि सड़क निर्माण कराना मेरा कार्य नहीं है। संबंधित विभाग व सरकार को समस्या से अवगत कराना सबकी जिम्मेवारी है। कस्टम ने संबंधित विभाग व सरकार को पत्र दिया है। इस दौरान स्थानीय उपायुक्त संतोष कुमार उपस्थित थे। श्री सिंह ने उन्हें सेवा पुस्तिका के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया।

प्रेसवार्ता करते मुख्य कस्टम आयुक्त

आयात-निर्यात को और गति देने पर होगी सार्थक : मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क पटना प्रक्षेत्र शिवनारायण सिंह ने इंडो-नेपाल बॉर्डर पर आयात-निर्यात की स्थिति व कार्यशैली का अवलोकन किया। इस दौरान भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के व्यापारियों, अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की, जिसमें बताया कि समन्वय स्थापित कर बेहतर कार्य किया जा सकता है। अधिकारी गंभीरता से कार्य करें, तो समाधान हो सकता है। देश की सबसे दूसरी बड़ी आधुनिक एकीकृत जांच चौकी तैयार है, परंतु व्यापारी व कर्मचारियों का माइंड सेट नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि आइसीपी का कार्य करने वाली एजेंसियों ने समस्या का निदान करने के लिए संयुक्त रूप से पहल नहीं की। त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेडर्स व सीएचए किलयरिंग एजेंटों के लिए अलग भवन देने की बात कही। इसके साथ ही बताया कि फिलहाल पड़ोसी देश नेपाल के पर्सा जिला सिरिसिया स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अर्द्धनिर्मित है, जिससे आयात-निर्यात सुचारू करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने करीब दो घंटों तक एसएसबी, नेपाल के प्रमुख व्यापारिक संगठन उद्योग वाणिच्य संघ, ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों व स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत की, जिसमें आयात-निर्यात को और गति देने पर सार्थक पहल करने की बात कही।